पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

दिनेश मंडल

बनाम

चैताली मजूमदार

2018 का विविध अपील संख्या 295

25 अगस्त, 2023

(माननीय न्यायमूर्ति श्री पी. बी. भजंत्री और माननीय न्यायमूर्ति श्री जितेंद्र कुमार)

विचार के लिए मुद्दा

1. क्या वैवाहिक वाद (तलाक) संख्या 560/2012 में माननीय अपर प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, कटिहार द्वारा पारित निर्णय सही है या नहीं?

2. क्या उत्तरदाता/पत्नी ने अपीलकर्ता/पति के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया?

3. क्या तलाक की याचिका प्रस्तुत करने के समय उत्तरदाता/पत्नी ने अपीलकर्ता/पति को दो वर्ष से अधिक समय से त्याग दिया है?

4. क्या उत्तरदाता/पत्नी व्यभिचार में रह रहा है और उसने विवाह संपन्न होने के बाद, अपने पति/पत्नी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के साथ स्वैच्छिक यौन संबंध बनाए हैं?

5. क्या अपीलकर्ता/पति तलाक की डिक्री प्राप्त करने का हकदार है?

हेडनोट्स

पारिवारिक न्यायालय अधिनियम, 1984- धारा 19(1)- हिंदू विवाह अधिनियम, 1955- धारा 13(1)(ia) और (ib)- तलाक- क्रूरता और परित्याग- अपीलकर्ता/पति का विवाह उत्तरदाता/पत्नी के साथ वर्ष 1980 में हुआ था और विवाह से दो बच्चे पैदा हुए थे- विवाह संपन्न होने के बाद दोनों पक्षों ने सुखी और समृद्ध वैवाहिक जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिया- लेकिन, 1997 में उत्तरदाता/पत्नी ने अपीलकर्ता/पति का साथ छोड़ दिया और एक

अस्पताल के क्वार्टर में रहने लगी- इससे पहले तलाक की याचिका अपीलकर्ता/पति और उत्तरदाता/पत्नी द्वारा मामले में उपस्थित न होने के कारण खारिज कर दी गई थी।

अभिनिर्धारित किया: वाद में, इस बात का कोई तर्क नहीं है कि तलाक के लिए शिकायत प्रस्तुत करते समय उत्तरदाता/पत्नी ने कितने वर्षों से अपीलकर्ता/पति का परित्याग किया है - पिछली तलाक याचिका में परित्याग का आधार नहीं बताया गया था - अपीलकर्ता/पति यह साबित करने में विफल रहा है कि उत्तरदाता/पत्नी ने वर्तमान याचिका प्रस्तुत करते समय दो वर्षों से अधिक समय के लिए सहवास को स्थायी रूप से समाप्त करने के इरादे से उसकी सहमति के बिना और उचित कारण के बिना उसे त्याग दिया है - प्रतिवादी/उत्तरदाता के व्यभिचारी जीवन के संबंध में कोई तर्क नहीं दिया गया है, न ही कथित व्यभिचारी को विद्वान पारिवारिक न्यायालय के समक्ष उत्तरदाता के रूप में पक्षकार बनाया गया है - — दलीलों से परे प्रस्तुत साक्ष्य अस्वीकार किए जाने योग्य हैं और याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई राहत प्रदान करने के लिए उन पर विचार नहीं किया जा सकता है— दलीलें और विवरण न्यायालय को विचारण में पक्षकारों के अधिकारों का निर्णय करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हैं—इसलिए, दलीलें न्यायालय के लिए संबंधित विवाद को कम करने और संबंधित पक्षों को मुद्दे के प्रश्न से अवगत कराने में अधिक सहायक हैं, ताकि पक्षकार उक्त मुद्दे पर उचित साक्ष्य प्रस्तुत कर सकें— दलीलें और मुद्दे पक्षों के बीच वास्तविक विवाद का पता लगाने, संघर्ष के क्षेत्र को कम करने और यह देखने के लिए हैं कि दोनों पक्ष कहाँ भिन्न हैं— अपील में कोई भी योग्यता नहीं है जो आक्षेपित निर्णय में किसी भी हस्तक्षेप को उचित ठहराती है—पारिवारिक न्यायालय ने तलाक की मांग करने वाले अपीलकर्ता के वैवाहिक मामले को सही ढंग से खारिज कर दिया है—अपील खारिज, आक्षेपित निर्णय, बरकरार। **(कंडिका 61, 62, 64, 65, 66, 71)**

न्याय दृष्टान्त

डॉ. नारायण गणेश दास्ताने बनाम सुचेता नारायण दास्ताने, **(1975) 2 एससीसी 326;** शोभा रानी बनाम मधुकर रेड्डी, **एआईआर 1988 एससी 121;** ए. जयचंद्र बनाम अनिल कौर, **2005(2) एससीसी 22;** गणनाथ पटनायक बनाम उड़ीसा राज्य, **(2002) 2 एससीसी 619;** हरभजन सिंह मोंगा बनाम अमरजीत कौर, **1985 एससीसी ऑनलाइन एमपी 83;** उमा वंती बनाम अर्जन देव, **1995 एससीसी ऑनलाइन पी एंड एच 56;** श्रीमती रीता निझावन बनाम श्री बाल कृष्ण निझावन, **आईएलआर (1973) I दिल्ली 944;** समर घोष बनाम जया घोष, **(2007) 4 एससीसी 511;** रवि कुमार बनाम जुमला देवी, **2010 एससीसीआर 265;** रामचंदर बनाम अनंता, **(2015) 11 एससीसी 539;** विनीता सक्सेना बनाम पंकज पंडित, **(2006) 3 एससीसी 778;** बिपिनचंद्र जयसिंहबाई शाह बनाम प्रभावती, **एआईआर 1957 एससी 176;** लछमन उतमचंद कृपलानी बनाम मीना, **एआईआर 1964 एससी 40;** सावित्री पांडे बनाम प्रेम चंद्र पांडे, **2002(2) एससीसी 73;** देबानंद तामुली बनाम काकुमोनी काताकी, **(2022) 5 एससीसी 459;** नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम नरेशकुमार बद्रीकुमार जगद एवं अन्य, **(2011) 12 एससीसी 695;** ट्रोजन एंड कंपनी बनाम नागप्पा चेट्टियार, **एआईआर 1953 एससी 235,** महाराष्ट्र राज्य बनाम हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, **(2010) 4 एससीसी 518;** कल्याण सिंह चौहान बनाम सी.पी. जोशी, **(2011) 11 एससीसी 786;** प्रकाश रतन लाल बनाम मनके राम, **आईएलआर (2010) III दिल्ली 315;** राम सरूप गुप्ता बाय एलआर बनाम बिशुन नारायण इंटर कॉलेज, **(1987) 2 एससीसी 555;** हरिहर प्रसाद सिंह बनाम बाल्मीकि प्रसाद सिंह, **(1975) 1 एससीसी 212** बच्चाज नाहर बनाम नीलिमा मंडल एवं अन्य, **(2008) 17 एससीसी 491**— पर भरोसा किया गया।

अधिनियमों की सूची

पारिवारिक न्यायालय अधिनियम, 1984; हिंदू विवाह अधिनियम, 1955

मुख्य शब्दों की सूची

क्रूरता, परित्याग, व्यभिचारी जीवन, व्यभिचार, दलीलें, मुद्दे, दलीलों से परे प्रस्तुत साक्ष्य अस्वीकार किए जाने योग्य हैं और राहत प्रदान करने के लिए उन पर विचार नहीं किया जा सकता है।

प्रकरण से उत्पन्न

वैवाहिक वाद (तलाक) संख्या 560/2012 में अपर प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, कटिहार द्वारा पारित निर्णय से।

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

अपीलकर्ता की ओर से: श्री किरण सिन्हा, अधिवक्ता।

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट बनाया गया: आभाष चंद्र, अधिवक्ता।

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2018 की विविध अपील सं 295

==

दिनेश मंडल, पिता स्वर्गीय ब्रिस्पति मंडल उर्फ़ बहस्पति मंडल निवासी मोहल्ला- रेलवे न्यू कॉलोनी, क्वार्टर सं 364 (डी), थाना- सहायक कटिहार, जिला- कटिहार

... ...अपीलकर्ता/वादी

बनाम

चैताली मजूमदार पति दिनेश मंडल, पिता स्वर्गीय मुकुंद लाल मजूमदार वर्तमान में- ए एन एम पी पी कार्यक्रम सदर अस्पताल, कटिहार

... ...उत्तरदाता /प्रतिवादी

==

उपस्थितिः

अपीलकर्ता/ओं के लिए : श्री किरण सिन्हा

उत्तरदाता/ओं के लिए : कोई नहीं

==

कोरमः माननीय न्यायमूर्ति श्री पी.बी. भजंत्री

और

माननीय न्यायमूर्ति श्री जितेंद्र कुमार

सी.ए.वी. निर्णय

(द्वाराः न्यायमूर्ति श्री जितेंद्र कुमार)

दिनांकः 25-08-2023

वर्तमान अपील परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 19(1) के अंतर्गत दायर की गई है, जिसमें कटिहार के विद्वान अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय द्वारा दिनांक 18.04.2017 को पारित निर्णय को चुनौती दी गई है, जो कि वैवाहिक मामले (तलाक) सं 560/2012 में पारित किया गया था, जिसमें धारा 13(1)(i) के अंतर्गत याचिका, जिसमें तलाक का डिक्री मांगा गया था, को *एकपक्षीय* रूप से खारिज कर दिया गया।

2. अपीलकर्ता/वादी के अभिवचनों के अनुसार, उनकी शादी उत्तरदाता के साथ वर्ष 1980 में हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार हुई थी और इस विवाह से दो संतानें हुईं, एक पुत्र, देवाशीष मंडल, जिसकी आयु लगभग 27 वर्ष है, और दूसरी पुत्री, चंद्रानी मंडल, जिसकी आयु लगभग 25 वर्ष है। यह भी अभिकथित है कि विवाह के पश्चात् दोनों पक्षों ने सुखी और समृद्ध वैवाहिक जीवन शुरू किया। लेकिन, वर्ष 1997 में, प्रतिवादी/उत्तरदाता ने अपीलकर्ता/वादी का साथ छोड़ दिया और अस्पताल के एक क्वार्टर में रहने लगी।

अपीलकर्ता/वादी ने प्रतिवादी/उत्तरदाता के व्यवहार को सुधारने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। यह भी अभिकथित है कि प्रतिवादी/उत्तरदाता ने विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में शिकायत वाद सं. 1249/2000 दायर की, जिसमें यातना और उत्पीड़न का आरोप लगाया गया, और यह शिकायत अभी भी लंबित है, तथा दोनों पक्षों के बीच वैवाहिक बंधन पूरी तरह से टूट चुका है। यह भी अभिकथित है कि अपीलकर्ता/वादी ने वैवाहिक बंधन को सुधारने के लिए कई प्रयास किए, परंतु प्रतिवादी/उत्तरदाता ने अपीलकर्ता का साथ नकार दिया। यह भी अभिकथित है कि प्रतिवादी/उत्तरदाता द्वारा किए गए व्यवहार और परिस्थितियों ने अपीलकर्ता के लिए अपमानजनक स्थिति उत्पन्न की है और मानसिक क्रूरता का कारण बनी है, क्योंकि प्रतिवादी/उत्तरदाता ने अपीलकर्ता को झूठे आपराधिक मामले में फंसाया, जिसके कारण अपीलकर्ता/वादी का जीवन दुखदायी हो गया है और वह निजी और सार्वजनिक जीवन में अपमानित महसूस कर रहा है। अतः, अपीलकर्ता/वादी प्रतिवादी/उत्तरदाता के साथ रहने में असमर्थ है। यह भी सूचित किया गया है कि इससे पहले अपीलकर्ता/वादी द्वारा कटिहार के विद्वान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में वैवाहिक वाद सं 30/2000 दायर किया गया था, जिसमें प्रतिवादी/उत्तरदाता ने उपस्थित होकर अपना लिखित कथन दायर किया था। सुलह की कार्यवाही भी आयोजित की गई थी। हालांकि, प्रतिवादी/उत्तरदाता ने अपीलकर्ता के साथ वैवाहिक जीवन जीने के लिए पूरी तरह से इंकार कर दिया था। यह भी अभिकथित है कि उक्त वैवाहिक वाद/मुकदमा अपीलकर्ता/वादी द्वारा उचित पैरवी न करने के कारण खारिज हो गया और यह वाद अंतिम रूप से समाप्त नहीं हो सका। यह भी अभिकथित है कि उनका विवाह अपूरणीय रूप से टूट चुका है और विवाह में कोई भावनात्मक आधार शेष नहीं है। वैवाहिक बंधन अब सुधार से परे है और विवाह केवल नाममात्र का रह गया है। यह भी अभिकथित है कि प्रतिवादी/उत्तरदाता पिछले लगभग 15 वर्षों से अपीलकर्ता/वादी के साथ

अलग रह रही है और इसलिए, अपीलकर्ता/वादी का दावा है कि वह दोनों पक्षों के बीच विवाह को विच्छेद करने हेतु तलाक की डिक्री का हकदार है।

3. सूचना देने पर, उत्तरदाता उपस्थित नहीं हुई। अतः, उनके विरुद्ध *एकपक्षीय* कार्यवाही की गई। *एकपक्षीय* सुनवाई के दौरान, वादी/अपीलकर्ता की ओर से निम्नलिखित तीन साक्षियों की जांच की गई:

i) **अ.सा.-1** - परदेशी कामती

ii) **अ.सा.-2** - सब्जो साची घोष

iii) **अ.सा.-3** - दिनेश मंडल, जो स्वयं वादी है

4. अपीलकर्ता/वादी ने निम्नलिखित दस्तावेजों को भी प्रदर्श के रूप में प्रस्तुत किया:

i) **प्रदर्श सं. 1** - वैवाहिक वाद सं 30/2000 के आदेश पत्र।

ii) **प्रदर्श सं. 2** - वैवाहिक याचिका सं 30/2000 की एक प्रति।

5. परदेशी कामती, जिनकी अ.सा.-1 के रूप में जांच की गई, दोनों पक्षों से परिचित हैं। उनके द्वारा शपथपत्र के माध्यम से दायर मुख्य परीक्षण में, उन्होंने वादी/अपीलकर्ता द्वारा अपनी याचिका में किए गए कथनों को दोहराया। उन्होंने यह भी बयान दिया कि प्रतिवादी/उत्तरदाता एक सरकारी अस्पताल में नर्स के रूप में कार्यरत है और वह पिछले 19 वर्षों से वादी/अपीलकर्ता से अलग रह रही है, तथा दोनों पक्षों के बीच वैवाहिक जीवन पूरी तरह समाप्त हो चुका है। न्यायालय के प्रश्न के उत्तर में, उन्होंने बयान दिया कि उन्होंने कभी भी प्रतिवादी/उत्तरदाता, चैताली मजूमदार, से बात नहीं की। उन्होंने केवल एक बार वर्ष 1998 में वादी/अपीलकर्ता के घर पर उत्तरदाता को देखा था, जब वहां विवाद हो रहा था।

6. सब्जो साची घोष, जिनकी अ.सा.-2 के रूप में जांच की गई, भी दोनों पक्षों से परिचित हैं। उनके द्वारा शपथपत्र के माध्यम से दायर मुख्य परीक्षण में, उन्होंने

वादी/अपीलकर्ता द्वारा दायर याचिका में किए गए कथनों को दोहराया। न्यायालय के प्रश्न के उत्तर में, उन्होंने बयान दिया कि वह वादी/अपीलकर्ता, दिनेश मंडल, के पड़ोसी हैं। उन्होंने यह भी बयान दिया कि वह और वादी/अपीलकर्ता वर्ष 1996 से रेलवे में कार्यरत हैं। उन्होंने यह भी बयान दिया कि उन्हें नहीं पता कि प्रतिवादी/उत्तरदाता वादी/अपीलकर्ता से अलग क्यों रह रही है।

7. अ.सा.-3, दिनेश मंडल, स्वयं वादी/अपीलकर्ता हैं। उनके द्वारा शपथपत्र के माध्यम से दायर मुख्य परीक्षण में, उन्होंने भी अपनी याचिका में किए गए कथनों को दोहराया। उक्त शपथपत्र में, उन्होंने यह भी बयान दिया कि उत्तरदाता-पत्नी (जो यहां प्रतिवादी है) का एक मनोज कुमार मंडल के साथ अवैध संबंध है। हालांकि, उत्तरदाता-पत्नी के मनोज कुमार मंडल के साथ अवैध संबंध का यह आरोप वादपत्र में अभिकथित नहीं है। न्यायालय के समक्ष, उन्होंने साक्ष्य दिया कि उन्होंने पहले भी विवाह विच्छेद के लिए एक तलाक वाद, वैवाहिक वाद सं. 30/2000, दायर किया था, लेकिन उसे अभियोजन न होने के कारण खारिज कर दिया गया। उन्होंने यह भी बयान दिया कि पहले की याचिका में भी विवाह विच्छेद के लिए वही आधार लिया गया था। उन्होंने यह भी बयान दिया कि उत्तरदाता/पत्नी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए के तहत दायर शिकायत वाद खारिज हो चुका है। हालांकि, उन्होंने इस दावे के समर्थन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया और यह स्पष्ट नहीं है कि शिकायत कैसे खारिज हुई।

8. प्रदर्श-1, जो कि पिछली तलाक याचिका सं. 30/2000 का आदेश पत्र है, दर्शाता है कि 20.05.2002 को, तलाक याचिका को वादी/अपीलकर्ता और उत्तरदाता/प्रतिवादी द्वारा मामले में उपस्थित न होने के कारण दोषपूर्ण करार देते हुए खारिज कर दिया गया था।

9. प्रदर्श-2, वैवाहिक वाद सं. 30/2000 की एक प्रति है, जो वादी/अपीलकर्ता द्वारा वर्ष 2000 में विवाह विच्छेद के लिए दायर की गई थी जो अनुपस्थिति के कारण खारिज हो गई थी। याचिका के अनुसार, वादी/अपीलकर्ता ने उत्तरदाता/पत्नी के एक मनोज

कुमार मंडल के साथ व्यभिचार का अभिकथन किया था, जिसे याचिका में उत्तरदाता सं 2 के रूप में शामिल किया गया था। हालांकि, वर्तमान तलाक याचिका में ऐसा कोई अभिकथन नहीं किया गया है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि पिछली याचिका में, उन्होंने परित्याग या क्रूरता को तलाक के आधार के रूप में अभिकथित नहीं किया था। पिछली वैवाहिक याचिका में केवल व्यभिचार को तलाक के आधार के रूप में अभिकथित किया गया था।

10. अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य और वादी/अपीलकर्ता की ओर से प्रस्तुत तर्कों पर विचार करने के पश्चात्, विद्वान परिवार न्यायालय ने *एकपक्षीय* रूप से वाद को खारिज कर दिया, यह मानते हुए कि अपीलकर्ता/वादी उत्तरदाता-पत्नी द्वारा उनके विरुद्ध कथित रूप से की गई क्रूरता को साबित करने में विफल रहे। विद्वान परिवार न्यायालय ने यह भी पाया कि वादी (जो यहां अपीलकर्ता हैं) द्वारा उत्तरदाता-पत्नी (जो यहां उत्तरदाता हैं) के विरुद्ध परित्याग का आधार भी साबित नहीं हुआ। व्यभिचार के संबंध में दिए गए साक्ष्य के बारे में, साक्ष्य के रूप में दायर मुख्य परीक्षण को विद्वान परिवार न्यायालय ने यह माना कि यह साक्ष्य अभिवचनों से परे है, क्योंकि इसे अपीलकर्ता/वादी द्वारा वादपत्र में अभिकथित नहीं किया गया था।

11. अपीलकर्ता/वादी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि विद्वान परिवार न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध अभिवचनों और साक्ष्यों की उचित समीक्षा करने में विफलता दिखाई है और इसलिए विद्वान परिवार न्यायालय ने गलत रूप से यह निष्कर्ष निकाला कि अपीलकर्ता/वादी उत्तरदाता-पत्नी के विरुद्ध क्रूरता, परित्याग और व्यभिचार को साबित करने में विफल रहे, जिसके आधार पर तलाक की डिक्री प्राप्त की जा सकती थी।

12. उत्तरदाता, सूचना देने के बावजूद, इस अपील का विरोध करने के लिए उपस्थिति नहीं हुई।

13. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता की ओर से किए गए अभिवचनों और प्रस्तुतियों के दृष्टिगत, इस न्यायालय के विचार के लिए निम्नलिखित बिंदु उत्पन्न होते हैं:

(i) क्या उत्तरदाता-पत्नी ने अपीलकर्ता/वादी के साथ क्रूरता का व्यवहार किया;

(ii) क्या उत्तरदाता-पत्नी ने तलाक याचिका प्रस्तुत करने के समय दो वर्ष से अधिक समय तक अपीलकर्ता/वादी को परित्यक्त किया;

(iii) क्या उत्तरदाता-पत्नी व्यभिचार में रह रही है और क्या उसने विवाह के पश्चात् अपने पति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के साथ स्वेच्छा से यौन संबंध स्थापित किया;

(iv) क्या अपीलकर्ता/वादी तलाक की डिक्री प्राप्त करने का हकदार है;

14. इस अभिवचन के दृष्टिगत कि वर्तमान तलाक याचिका से पहले, अपीलकर्ता-वादी ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 के तहत वैवाहिक वाद सं 30/2000 तलाक के लिए दायर किया था और यह वाद दिनांक 20.05.2002 को अपीलकर्ता और उत्तरदाता द्वारा मामले में उपस्थित न होने के कारण खारिज कर दिया गया था, एक प्रारंभिक प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या वर्तमान तलाक याचिका प्रतिबंधित है या नहीं। इस प्रश्न पर पहले विचार किया जाना आवश्यक है। इस संदर्भ में, सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश IX के नियम 3 का उल्लेख करना प्रासंगिक होगा, जिसके अनुसार, जब वाद सुनवाई के लिए बुलाए जाने पर कोई भी पक्ष उपस्थित नहीं होता, तो न्यायालय यह आदेश दे सकता है कि वाद खारिज कर दिया जाए। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश IX के नियम 4 के अनुसार, जहां वाद नियम 2 या नियम 3 के तहत खारिज कर दिया जाता है, वहां वादी को नया वाद दायर करने की स्वतंत्रता है या वह वाद की बहाली के लिए आवेदन कर सकता है, बशर्ते यह परिसीमा कानून के अधीन हो। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश IX के नियम 3 और 4 निम्नलिखित हैं:

*"3. **जहां कोई भी पक्ष उपस्थित नहीं होता, वाद खारिज किया जाए।**- जहां वाद सुनवाई के लिए बुलाए जाने पर कोई भी पक्ष*

उपस्थित नहीं होता, वहां न्यायालय यह आदेश दे सकता है कि वाद खारिज कर दिया जाए।

4. ***वादी नया वाद दायर कर सकता है या न्यायालय वाद को पुनः दर्ज कर सकता है।****- जहां वाद नियम 2 या नियम 3 के तहत खारिज कर दिया जाता है, वहां वादी (सीमा-विधि के अधीन) नया वाद दायर कर सकता है; या वह खारिज करने के आदेश को रद्द करने के लिए आवेदन कर सकता है, और यदि वह न्यायालय को संतुष्ट करता है कि नियम 2 में उल्लिखित विफलता या उसकी अनुपस्थिति के लिए पर्याप्त कारण था, तो न्यायालय खारिज करने के आदेश को रद्द करने का आदेश देगा और वाद के साथ आगे बढ़ने के लिए एक दिन नियत करेगा।"*

15. इस प्रकार, हम पाते हैं कि यदि दोनों पक्षों की अनुपस्थिति के कारण वाद खारिज कर दिया जाता है, तो वादी के पास दो विकल्प हैं - या तो वह सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश IX के नियम 4 के तहत आवेदन दायर कर खारिज करने के आदेश को रद्द करवाकर वाद की बहाली कर सकता है या नया वाद दायर कर सकता है।

16. वर्तमान मामले में, अपीलकर्ता/वादी ने नया वाद दायर करना पसंद किया है। अतः, वाद प्रतिबंधित नहीं है। यह बनाए रखने योग्य है।

17. अब हम उन बिंदुओं पर विचार करें, जो इस न्यायालय द्वारा विचार के लिए पहले से ही निर्धारित किए गए हैं।

18. हालांकि, इन विचारणीय बिंदुओं पर चर्चा करने से पहले, वैवाहिक मामलों में साक्ष्य के बोझ और साक्ष्य के मानक के संबंध में प्रामाणिक न्यायिक निर्णयों या केस कानूनों को देखना अनिवार्य है।

19. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **डॉ. नारायण गणेश दस्ताने बनाम सुचेता नारायण दस्ताने**, जैसा कि **1975 (2) एस.सी.सी. 326** में प्रतिवेदित किया गया है, में वैवाहिक मामलों में साक्ष्य के बोझ की प्रकृति पर विस्तार से चर्चा की है और इसमें निर्धारित कानून अभी भी लागू है। इस मामले के कंडिका 23 में, **माननीय सर्वोच्च न्यायालय** ने टिप्पणी की है कि, निस्संदेह, याचिकाकर्ता पर अपने मामले को स्थापित करने का बोझ होना चाहिए, क्योंकि सामान्य रूप से, वह पक्ष जो किसी तथ्य की पुष्टि करता है, उस पर साक्ष्य का बोझ होता है, न कि उस पक्ष पर जो इसका खंडन करता है। यह सिद्धांत सामान्य बुद्धि के अनुरूप है क्योंकि सकारात्मक तथ्य को साबित करना नकारात्मक तथ्य को साबित करने से कहीं अधिक आसान है। इसलिए, याचिकाकर्ता को यह साबित करना होगा कि उत्तरदाता ने उसके साथ क्रूरता का व्यवहार किया है।

20. साक्ष्य के मानक के संदर्भ में, हम पाते हैं कि हिंदू विवाह अधिनियम के तहत उत्तरदाता के कदाचार को वर्णित करने के लिए "वैवाहिक अपराध" शब्दों के उपयोग के कारण कुछ भ्रांति उत्पन्न हुई थी। यही कारण है कि **माननीय सर्वोच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ** के प्रामाणिक निर्णय, **डॉ. नारायण गणेश दस्ताने बनाम सुचेता नारायण दस्ताने, जैसा कि 1975 (2) एस.सी.सी. 326** में प्रतिवेदित किया गया है, से पहले परस्पर विरोधी मत थे। एक मत के अनुसार, वैवाहिक मामले सिविल प्रकृति के हैं और इसलिए ऐसे मामलों में साक्ष्य का मानक संभावनाओं की प्रबलता होगा, जबकि दूसरे मत के अनुसार, हिंदू विवाह अधिनियम में "वैवाहिक अपराध" शब्द के उपयोग के दृष्टिगत, साक्ष्य का मानक उचित संदेह से परे साक्ष्य होना चाहिए। हालांकि, **डॉ. नारायण गणेश दस्ताने मामले (उपर्युक्त)** में, **माननीय सर्वोच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ** ने स्पष्ट रूप से माना कि वैवाहिक मामले दीवानी प्रकृति के हैं और हिंदू विवाह अधिनियम के तहत वैवाहिक मामलों की सुनवाई में साक्ष्य का मानक संभावनाओं की प्रबलता होगा, न कि उचित संदेह से परे साक्ष्य, जो आपराधिक सुनवाइयों में लागू होता है। **माननीय सर्वोच्च न्यायालय** ने **डॉ. नारायण गणेश दस्ताने**

मामले (उपर्युक्त) के कंडिका 24 में टिप्पणी की है कि दीवानी कार्यवाहियों को नियंत्रित करने वाला सामान्य नियम यह है कि एक तथ्य को तब स्थापित माना जा सकता है, जब वह संभावनाओं की प्रबलता द्वारा साबित हो। इसका कारण यह है कि साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3 के अंतर्गत, एक तथ्य को तब साबित माना जाता है, जब न्यायालय या तो उसका अस्तित्व मानता है या उसका अस्तित्व इतना संभावित मानता है कि एक विवेकपूर्ण व्यक्ति को, विशेष मामले की परिस्थितियों में, यह मान लेना चाहिए कि वह तथ्य मौजूद है। इस प्रकार, किसी तथ्य के अस्तित्व के बारे में विश्वास संभावनाओं के संतुलन पर आधारित हो सकता है। एक विवेकपूर्ण व्यक्ति, जो किसी तथ्य की स्थिति के संबंध में परस्पर विरोधी संभावनाओं का सामना करता है, यह मान लेगा कि तथ्य मौजूद है, यदि वह विभिन्न संभावनाओं का वजन करने पर पाता है कि प्रबलता उस विशेष तथ्य के अस्तित्व के पक्ष में है। एक विवेकपूर्ण व्यक्ति की तरह, न्यायालय भी इस परीक्षा को लागू करता है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि विवादित तथ्य साबित हो सकता है या नहीं। इस प्रक्रिया का पहला चरण संभावनाओं को निर्धारित करना है, दूसरा उन्हें तौलना है, हालांकि ये दोनों प्रायः आपस में मिल सकते हैं। असंभव को पहले चरण में हटा दिया जाता है, असंभाव्य को दूसरे चरण में। संभावनाओं की विस्तृत श्रृंखला के भीतर, न्यायालय को प्रायः एक कठिन विकल्प करना पड़ता है, लेकिन यही विकल्प अंततः यह निर्धारित करता है कि संभावनाओं की प्रबलता कहाँ है।संभावनाओं की विस्तृत श्रृंखला में न्यायालय के लिए अक्सर एक कठिन विकल्प चुनना होता है, लेकिन यही विकल्प अंततः यह निर्धारित करता है कि संभावनाओं की प्रधानता कहाँ है। लेकिन चाहे मामला क्रूरता का हो या प्रोनोट पर ऋण का, लागू होने वाला परीक्षण यह है कि क्या संभावनाओं की अधिकता के आधार पर संबंधित तथ्य सिद्ध होता है। दीवानी मामलों में, सामान्यतः, यह पता लगाने के लिए प्रमाण का मानक होता है कि क्या साक्ष्य का भार मुक्त हुआ है।

21. वैवाहिक मामलों में "उचित संदेह से परे साक्ष्य" के उपयोग को खारिज करते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **डॉ. नारायण गणेश दस्ताने मामले (उपर्युक्त)** के कंडिका 25 में टिप्पणी की है कि उचित संदेह से परे साक्ष्य उच्चतर मानक द्वारा साक्ष्य है, जो सामान्य रूप से आपराधिक सुनवाइयों या अर्ध-आपराधिक प्रकृति के मुद्दों की जांच से संबंधित सुनवाइयों को नियंत्रित करता है। आपराधिक सुनवाई में विषय की स्वतंत्रता शामिल होती है, जिसे केवल संभावनाओं की प्रबलता के आधार पर छीना नहीं जा सकता। यदि संभावनाएँ इतनी सूक्ष्म रूप से संतुलित हैं कि एक तर्कसंगत, न कि अस्थिर, मन यह नहीं पा सकता कि प्रबलता कहाँ है, तो साबित होने वाले तथ्य के अस्तित्व के संबंध में संदेह उत्पन्न होता है और इस तरह के उचित संदेह का लाभ अभियुक्त को जाता है। विशुद्ध रूप से दिवानी प्रकृति की सुनवाइयों में ऐसी विचारों को लागू करना गलत है। **डॉ. नारायण गणेश दस्ताने मामले (उपर्युक्त)** के कंडिका 26 में, **माननीय सर्वोच्च न्यायालय** ने आगे टिप्पणी की है कि हिंदू विवाह अधिनियम के तहत कहीं भी यह आवश्यक नहीं है कि याचिकाकर्ता को अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित करना होगा। धारा 23 न्यायालय को यह शक्ति प्रदान करती है कि यदि वह इसके उप-धारा (1) के खंड (क) से (ङ) में उल्लिखित मामलों पर "संतुष्ट" है, तो डिक्री पारित कर सकता है। यह देखते हुए कि अधिनियम के तहत कार्यवाहियाँ मूल रूप से दिवानी प्रकृति की हैं, "संतुष्ट" शब्द का अर्थ "संभावनाओं की प्रबलता पर संतुष्ट" होना चाहिए, न कि "उचित संदेह से परे संतुष्ट"। धारा 23 दिवानी मामलों में साक्ष्य के मानक को परिवर्तित नहीं करती।

22. **माननीय सर्वोच्च न्यायालय** ने **डॉ. नारायण गणेश दस्ताने मामले (उपर्युक्त)** के कंडिका *27* में आगे टिप्पणी की है कि वैवाहिक मामलों में साक्ष्य के मानक के संबंध में भ्रांति शायद उत्तरदाता के आचरण को "वैवाहिक अपराध" के रूप में ढीले-ढाले वर्णन के कारण उत्पन्न होती है। एक पति या पत्नी के ऐसे कृत्य, जो वैवाहिक बंधन की अखंडता को क्षति पहुँचाने के लिए किए जाते हैं, का सामाजिक महत्त्व है। विवाह करना या न करना

और यदि करना तो किससे, यह एक निजी मामला हो सकता है, लेकिन वैवाहिक बंधन को तोड़ने की स्वतंत्रता निजी नहीं है। समाज का विवाह संस्था में हित है और इसलिए गलती करने वाले पति या पत्नी को केवल एक डिफॉल्टर के रूप में नहीं, बल्कि एक अपराधी के रूप में माना जाता है। लेकिन यह सामाजिक दर्शन, हालाँकि इसका संबंध इस आवश्यकता से हो सकता है कि किसी आरोप को विवाह विच्छेद के आधार के रूप में स्वीकार करने से पहले उसका स्पष्टतम प्रमाण होना चाहिए, वैवाहिक मामलों में प्रमाण के मानक पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

23. **माननीय सर्वोच्च न्यायालय** ने **शोभा रानी बनाम मधुकर रेड्डी**, जैसा कि **ए.आई.आर. 1988 एस.सी. 121** में प्रतिवेदित किया गया है, के कंडिका 10 में भी टिप्पणी की है कि यह देखते हुए कि हिंदू विवाह अधिनियम के तहत कार्यवाहियाँ मूल रूप से दिवानी प्रकृति की हैं, "संतुष्ट" शब्द का अर्थ "संभावनाओं की प्रबलता पर संतुष्ट" होना चाहिए, न कि "उचित संदेह से परे संतुष्ट"। अधिनियम की धारा 23 दिवानी मामलों में साक्ष्य के मानक को परिवर्तित नहीं करती।

24. **माननीय सर्वोच्च न्यायालय** ने **ए. जयचंद्रा बनाम अनील कौर**, जैसा कि **2005(2) एस.सी.सी. 22** में प्रतिवेदित किया गया है, के कंडिका 10 में टिप्पणी की है कि विवाह जैसे नाजुक मानवीय संबंध में, मामले की संभावनाओं को देखना पड़ता है। छाया रहित संदेह से परे साक्ष्य की अवधारणा आपराधिक सुनवाइयों पर लागू होती है, न कि दिवानी मामलों पर और निश्चित रूप से पति-पत्नी जैसे नाजुक व्यक्तिगत संबंधों के मामलों पर। इसलिए, किसी मामले में संभावनाओं को देखना होगा और कानूनी क्रूरता को केवल तथ्य के रूप में ही नहीं, बल्कि शिकायतकर्ता पति या पत्नी के मन पर दूसरे पक्ष के कृत्यों या चूकों के प्रभाव के रूप में भी खोजना होगा। क्रूरता शारीरिक या भौतिक हो सकती है या मानसिक हो सकती है। शारीरिक क्रूरता में मूर्त और प्रत्यक्ष साक्ष्य हो सकते हैं, लेकिन मानसिक क्रूरता के मामले में एक साथ प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं हो सकते। उन मामलों में जहां

प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं हैं, न्यायालयों को साक्ष्य में लाए गए घटनाओं के मानसिक प्रक्रिया और मानसिक प्रभाव की जांच करने की आवश्यकता होती है। इस दृष्टिकोण से वैवाहिक विवादों में साक्ष्य पर विचार करना होगा।

25. माननीय केरल उच्च न्यायालय ने ए. जयचंद्रा मामले (उपर्युक्त) का उल्लेख करते हुए, मोहनदास पनिकर बनाम दक्षायणी, जैसा कि 2013 एस.सी.सी. ऑनलाईन के.ई.आर. 24493 में प्रतिवेदित किया गया है, के कंडिका 19 में टिप्पणी की है कि उपर्युक्त निर्णयों में निर्धारित सिद्धांत यह दोहराते हैं कि दिवानी मामलों में, संभावनाओं की प्रबलता वह मानक है जिसे मामले को साबित करने के लिए अपनाया जाना चाहिए। निस्संदेह, वैवाहिक मामले दिवानी कार्यवाहियाँ हैं और न्यायालय संभावनाओं की प्रबलता पर कार्य कर सकता है, विशेष रूप से व्यभिचार के मामलों में, क्योंकि इसमें प्रत्यक्ष साक्ष्य प्राप्त करना कठिन है।

26. अब हम बिंदुओं पर एक-एक करके विचार करें।

बिंदू सं 01

27. यह विचार करने से पहले कि क्या उत्तरदाता/पत्नी ने अपीलकर्ता-वादी-पति के साथ क्रूरता का व्यवहार किया है, यह देखना अनिवार्य होगा कि इस विषय पर वैधानिक प्रावधान और केस कानून क्या हैं।

28. हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1)(i-a) के तहत क्रूरता को तलाक के आधारों में से एक माना गया है। प्रावधानों के अनुसार, यदि दूसरा पक्ष याचिकाकर्ता के साथ क्रूरता का व्यवहार करता है, तो दोनों पक्षों में से किसी एक द्वारा प्रस्तुत याचिका पर विवाह को तलाक की डिक्री द्वारा भंग किया जा सकता है।

29. हालांकि, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1)(i-a) में प्रयुक्त "क्रूरता" शब्द को हिंदू विवाह अधिनियम के तहत परिभाषित नहीं किया गया है। लेकिन इस शब्द की व्याख्या **माननीय सर्वोच्च न्यायालय** द्वारा कई अवसरों पर की गई है।

30. **माननीय सर्वोच्च न्यायालय** ने **शोभा रानी बनाम मधुकर रेड्डी**, जैसा कि **ए.आई.आर. 1988 एस.सी. 121** में प्रतिवेदित किया गया है, के कंडिका 4 में टिप्पणी की है कि "क्रूरता" शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। वास्तव में इसे परिभाषित नहीं किया जा सकता था। यह शब्द मानवीय आचरण या व्यवहार के संबंध में प्रयुक्त हुआ है। यह वैवाहिक कर्तव्यों और दायित्वों के संबंध में आचरण है। यह एक पक्ष का ऐसा आचरण है जो दूसरे पक्ष को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। क्रूरता मानसिक या शारीरिक, जानबूझकर या अनजाने में हो सकती है। यदि यह शारीरिक है, तो न्यायालय को इसे निर्धारित करने में कोई समस्या नहीं होगी। यह तथ्य और डिग्री का प्रश्न है। यदि यह मानसिक है, तो समस्या उत्पन्न होती है। सबसे पहले, क्रूर व्यवहार की प्रकृति की जांच शुरू होनी चाहिए। दूसरा, पति या पत्नी के मन पर ऐसे व्यवहार का प्रभाव। क्या इससे यह उचित आशंका उत्पन्न हुई कि दूसरे के साथ रहना हानिकारक या नुकसानदेह होगा। अंततः, यह निष्कर्ष निकालने का मामला है, जिसमें आचरण की प्रकृति और शिकायतकर्ता पति या पत्नी पर इसके प्रभाव को ध्यान में रखा जाता है। हालांकि, कुछ मामले ऐसे हो सकते हैं जहां शिकायत किया गया आचरण स्वयं इतना खराब हो और प्रथम दृष्टया गैरकानूनी या अवैध हो। ऐसे मामलों में, दूसरे पति या पत्नी पर प्रभाव या हानिकारक प्रभाव की जांच करने या विचार करने की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे मामलों में, यदि आचरण स्वयं साबित हो जाता है या स्वीकार किया जाता है, तो क्रूरता स्थापित हो जाएगी।

31. **माननीय सर्वोच्च न्यायालय** ने **शोभा रानी मामले** (उपर्युक्त) के कंडिका 5 में आगे टिप्पणी की है कि यह ध्यान में रखना आवश्यक होगा कि हमारे आसपास के जीवन में उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ है। विशेष रूप से वैवाहिक कर्तव्यों और जिम्मेदारियों में, हम एक बड़ा बदलाव देखते हैं। वे घर-घर या व्यक्ति-दर-व्यक्ति अलग-अलग स्तर के होते हैं। इसलिए, जब एक पति या पत्नी अपने जीवनसाथी या रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता के व्यवहार की शिकायत करता है, तो न्यायालय को जीवन में मानक की खोज नहीं करनी चाहिए। एक

मामले में क्रूरता के रूप में कलंकित तथ्यों को दूसरे मामले में ऐसा नहीं माना जा सकता। आरोपित क्रूरता काफी हद तक उस जीवनशैली पर निर्भर हो सकती है जिसके पक्षकार आदी हैं या उनकी आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों पर। यह उनकी संस्कृति और मानवीय मूल्यों पर भी निर्भर हो सकता है, जिन्हें वे महत्व देते हैं। इसलिए, न्यायाधीशों और वकीलों को अपनी स्वयं की जीवन की धारणाओं को लागू नहीं करना चाहिए। वे उनके साथ समानांतर नहीं चल सकते। उनके और पक्षकारों के बीच पीढ़ीगत अंतर हो सकता है। बेहतर होगा यदि वे अपनी प्रथाओं और तौर-तरीकों को अलग रखें। यह भी बेहतर होगा यदि वे नजीरों पर कम निर्भर रहें। प्रत्येक मामला अलग हो सकता है। वे उन मनुष्यों के आचरण से संबंधित हैं जो सामान्यतः एक जैसे नहीं होते। मानवों में उस आचरण की कोई सीमा नहीं है जो क्रूरता का गठन कर सकता है। मानवीय व्यवहार, सहन करने की क्षमता या अक्षमता के आधार पर किसी भी मामले में क्रूरता का नया प्रकार उभर सकता है। ऐसा है क्रूरता का अद्भुत क्षेत्र।

32. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **शोभा रानी मामले (उपर्युक्त)** के कंडिका 17 में भी टिप्पणी की है कि जिस संदर्भ और ढांचे में "क्रूरता" शब्द का उपयोग धारा में किया गया है, उससे प्रतीत होता है कि क्रूरता में इरादा आवश्यक तत्व नहीं है। इस शब्द को वैवाहिक मामलों में सामान्य अर्थ में समझा जाना चाहिए। यदि आचरण या क्रूर कृत्य की प्रकृति से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इसका इरादा नुकसान पहुंचाना, उत्पीड़न करना या चोट पहुंचाना था, तो क्रूरता आसानी से स्थापित हो सकती है। लेकिन इरादे की अनुपस्थिति से मामले में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, यदि मानवीय मामलों में सामान्य अर्थ में, शिकायत किया गया कृत्य अन्यथा क्रूरता माना जा सकता है। पक्षकार को राहत इस आधार पर नहीं नकारी जा सकती कि जानबूझकर या इच्छित रूप से कोई दुर्व्यवहार नहीं हुआ।

33. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **गणनाथ पटनायक बनाम उड़ीसा राज्य**, जैसा कि **2002(2) एस.सी.सी. 619** में प्रतिवेदित किया गया है, में टिप्पणी की है कि क्रूरता की अवधारणा और इसका प्रभाव व्यक्ति-व्यक्ति पर भिन्न होता है, जो उस व्यक्ति की सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर भी निर्भर करता है। उपर्युक्त धारा के तहत अपराध के गठन के लिए "क्रूरता" को शारीरिक होने की आवश्यकता नहीं है। मानसिक यातना या असामान्य व्यवहार भी किसी दिए गए मामले में क्रूरता और उत्पीड़न के समान हो सकता है।

34. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **ए. जयचंद्रा बनाम अनील कौर**, जैसा कि **2005(2) एस.सी.सी. 22** में प्रतिवेदित किया गया है, के कंडिका 10 में टिप्पणी की है कि विवाह विच्छेद के आधार के रूप में क्रूरता को ऐसे जानबूझकर और अनुचित आचरण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो जीवन, अंग या स्वास्थ्य, शारीरिक या मानसिक, को खतरे में डालने वाला हो, या ऐसी उचित आशंका पैदा करता हो। मानसिक क्रूरता के प्रश्न को उस विशेष समाज के वैवाहिक संबंधों के मानदंडों, उनके सामाजिक मूल्यों, स्थिति, और जिस पर्यावरण में वे रहते हैं, के प्रकाश में विचार करना होगा। क्रूरता में मानसिक क्रूरता शामिल है, जो वैवाहिक गलती के दायरे में आती है। क्रूरता को शारीरिक होने की आवश्यकता नहीं है। यदि किसी पति या पत्नी के आचरण से यह स्थापित हो जाता है और/या वैध रूप से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि पति या पत्नी का व्यवहार ऐसा है कि यह दूसरे पति या पत्नी के मानसिक कल्याण के बारे में आशंका पैदा करता है, तो यह आचरण क्रूरता के समान है।

35. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **ए. जयचंद्रा मामले** (उपर्युक्त) के कंडिका 12 में आगे टिप्पणी की है कि क्रूरता का गठन करने के लिए, शिकायत किए गए आचरण को "गंभीर और वजनी" होना चाहिए, ताकि यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि याचिकाकर्ता पति या पत्नी से उचित रूप से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह दूसरे पति या पत्नी के

साथ रहे। यह वैवाहिक जीवन की "सामान्य टूट-फूट" से कहीं अधिक गंभीर होना चाहिए। परिस्थितियों और पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए, आचरण की जांच की जानी चाहिए ताकि यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि शिकायत किया गया आचरण वैवाहिक कानून में क्रूरता के समान है या नहीं। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, आचरण को कई कारकों की पृष्ठभूमि में विचार करना होगा, जैसे कि पक्षकारों की सामाजिक स्थिति, उनकी शिक्षा, शारीरिक और मानसिक स्थिति, रीति-रिवाज और परंपराएँ। ऐसी परिस्थितियों की सटीक परिभाषा देना या विस्तृत विवरण देना कठिन है, जो क्रूरता का गठन करेंगी। यह ऐसी प्रकृति का होना चाहिए जो न्यायालय के विवेक को संतुष्ट करे कि दूसरे पति या पत्नी के आचरण के कारण पक्षकारों के बीच संबंध इतने बिगड़ गए हैं कि उनके लिए मानसिक पीड़ा, यातना या संकट के बिना एक साथ रहना असंभव हो गया है, जिससे शिकायतकर्ता पति या पत्नी को तलाक प्राप्त करने का अधिकार मिले। क्रूरता का गठन करने के लिए शारीरिक हिंसा पूरी तरह से आवश्यक नहीं है और अथाह मानसिक पीड़ा और यातना देने वाला निरंतर आचरण अधिनियम की धारा 10 के अर्थ में क्रूरता का गठन कर सकता है। मानसिक क्रूरता में गंदी और अपमानजनक भाषा का उपयोग करके मौखिक दुरुपयोग और अपमान शामिल हो सकते हैं, जिससे दूसरे पक्ष की मानसिक शांति लगातार बाधित होती है।

36. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **ए. जयचंद्रा मामले** (उपर्युक्त) के कंडिका 13 में आगे टिप्पणी की है कि क्रूरता के आधार पर तलाक की याचिका से निपटने वाले न्यायालय को यह ध्यान में रखना होगा कि उसके सामने की समस्याएँ मानवों की हैं और पति या पत्नी के आचरण में मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों को तलाक की याचिका का निपटारा करने से पहले ध्यान में रखना होगा। चाहे वह कितना भी तुच्छ या मामूली हो, ऐसा आचरण दूसरे के मन में दर्द पैदा कर सकता है। लेकिन आचरण को क्रूरता कहने से पहले, यह एक निश्चित गंभीरता के स्तर को छूना चाहिए। गंभीरता का वजन करना न्यायालय का काम है। यह देखना होगा कि क्या आचरण ऐसा था कि कोई तर्कसंगत व्यक्ति इसे सहन नहीं करेगा।

यह विचार करना होगा कि क्या शिकायतकर्ता को सामान्य मानवीय जीवन के हिस्से के रूप में इसे सहन करने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए। प्रत्येक वैवाहिक आचरण, जो दूसरे को परेशानी का कारण बन सकता है, क्रूरता के समान नहीं हो सकता। दैनिक वैवाहिक जीवन में होने वाली मामूली झुंझलाहटें, पति-पत्नी के बीच झगड़े भी क्रूरता के समान नहीं हो सकते। वैवाहिक जीवन में क्रूरता निराधार प्रकार की हो सकती है, जो सूक्ष्म या क्रूर हो सकती है। यह शब्दों, इशारों या केवल मौन के माध्यम से हो सकती है, हिंसक या अहिंसक।

37. **हरभजन सिंह मोंगा बनाम अमरजीत कौर**, जैसा कि **1985 एस.सी.सी. ऑनलाईन एम.पी. 83** में प्रतिवेदित किया गया है, में **माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय** ने माना है कि दूसरे पति या पत्नी और उनके परिवार के सदस्यों को झूठे आपराधिक मामले में फंसाने के लिए आत्महत्या की धमकी देना भी क्रूरता के समान है।

38. **श्रीमती उमा वंती बनाम अर्जन देव**, जैसा कि **1995 एस.सी.सी. ऑनलाईन पी & एच 56** में प्रतिवेदित किया गया है, में **माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय** ने माना है कि अस्वस्थ मन या अन्य कारणों से पति या पत्नी का विचित्र व्यवहार भी क्रूरता के समान है। **माननीय न्यायालय** ने माना कि अपीलकर्ता का दैनिक व्यवहार ऐसा था जो उत्तरदाता की मानसिक शांति और सामंजस्य को बाधित करता था, जो निश्चित रूप से कानूनी क्रूरता के समान था। वह अस्वस्थ मन की हो या न हो, लेकिन उत्तरदाता द्वारा साबित किए गए उसके विचित्र व्यवहार के तरीके कानूनी क्रूरता का गठन करने के लिए पर्याप्त हैं। पति अपीलकर्ता के साथ शांति से नहीं रह सकता था। उसके विचित्र व्यवहार के तरीकों के कारण शांति हमेशा बाधित थी, और इसलिए यह अविश्वसनीय नहीं है कि उसका व्यवहार उसके लिए क्रूर था।

39. **श्रीमती रीता निझावन बनाम श्री बल कृष्ण निझावन**, जैसा कि **आई.एल.आर.(1973) I दिल्ली 944** में प्रतिवेदित किया गया है, में **माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय** ने माना है कि नपुंसकता या अन्य कारणों से यौन संबंध से इंकार करना

शिकायतकर्ता पति या पत्नी के लिए क्रूरता के समान है। **माननीय न्यायालय** ने यह भी टिप्पणी की कि यौन संबंध विवाह का आधार है और इसके बिना जोरदार और सामंजस्यपूर्ण यौन गतिविधि के बिना किसी भी विवाह को लंबे समय तक जारी रखना असंभव होगा। यह अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि विवाह में यौन गतिविधि का एक महिला के मन और शरीर पर अत्यंत अनुकूल प्रभाव पड़ता है। इसका परिणाम यह होता है कि यदि उसे उचित यौन संतुष्टि नहीं मिलती तो यह अवसाद और हताशा की ओर ले जाएगा। यह कहा गया है कि जब यौन संबंध खुशहाल और सामंजस्यपूर्ण होते हैं तो यह महिला के मस्तिष्क को जीवंत करता है, उसके चरित्र को विकसित करता है और उसकी जीवन शक्ति को तिगुना करता है। यह स्वीकार करना होगा कि यौन संबंधों में निराशाएँ विवाह के लिए सबसे घातक हैं।

40. **माननीय न्यायालय** ने **श्रीमती रीता निझावन मामले** (उपर्युक्त) में आगे टिप्पणी की है कि कानून अच्छी तरह से स्थापित है कि यदि विवाह के दोनों पक्षों में से कोई एक, स्वस्थ शारीरिक क्षमता होने के बावजूद, यौन संबंध से इंकार करता है, तो यह क्रूरता के समान होगा, जिससे दूसरे पक्ष को डिक्री का हकदार बनाया जाएगा। हमारी राय में, यह कानून में कोई अंतर नहीं करता कि यौन संबंध से इंकार उत्तरदाता की यौन कमजोरी के कारण है, जो उसे अपीलकर्ता के साथ यौन संबंध स्थापित करने में अक्षम बनाती है, या यह उत्तरदाता के जानबूझकर इंकार के कारण है; क्योंकि दोनों ही मामलों में परिणाम एक ही है, अर्थात् सामान्य यौन जीवन से वंचित होने के कारण अपीलकर्ता को हताशा और दुख, और इसलिए क्रूरता।

41. **माननीय सर्वोच्च न्यायालय** ने **समर घोष बनाम जया घोष**, जैसा कि **(2007) 4 एस.सी.सी. 511** में प्रतिवेदित किया गया है, के कंडिका 99 में, क्रूरता के बिंदु पर कई निर्णयों का उल्लेख और चर्चा करने के बाद टिप्पणी की है कि मानव मन अत्यंत जटिल है और मानव व्यवहार समान रूप से जटिल है। इसी तरह, मानव चतुराई की कोई सीमा नहीं

है, इसलिए, संपूर्ण मानव व्यवहार को एक परिभाषा में समाहित करना लगभग असंभव है। एक मामले में जो क्रूरता है, वह दूसरे मामले में क्रूरता नहीं हो सकती। क्रूरता की अवधारणा व्यक्ति-व्यक्ति पर निर्भर करती है, जो उसकी परवरिश, संवेदनशीलता के स्तर, शैक्षिक, पारिवारिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, वित्तीय स्थिति, सामाजिक स्तर, रीति-रिवाज, परंपराओं, धार्मिक विश्वासों, मानवीय मूल्यों और उनकी मूल्य प्रणाली पर निर्भर करती है।

42. **माननीय उच्चतम न्यायालय** ने आगे कहा है **समर घोष मामले (उपर्युक्त)** में कहा गया है कि मानसिक क्रूरता की अवधारणा की कोई व्यापक परिभाषा नहीं हो सकती है जिसके भीतर मानसिक क्रूरता के सभी प्रकार के मामलों को शामिल किया जा सके। **माननीय न्यायालय** ने कंडिका 100 में आगे कहा है कि मानसिक क्रूरता की अवधारणा स्थिर नहीं रह सकती है। यह समय के साथ, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और मूल्य प्रणाली आदि के माध्यम से आधुनिक संस्कृति के प्रभाव के साथ बदलने के लिए बाध्य है।अब जो मानसिक क्रूरता हो सकती है वह समय बीतने के बाद मानसिक क्रूरता नहीं रह सकती है या इसके विपरीत भी।वैवाहिक मामलों में मानसिक क्रूरता को निर्धारित करने के लिए कभी भी कोई स्ट्रैटजैकेट फॉर्मूला या निश्चित मापदंड नहीं हो सकते हैं।मामले में निर्णय लेने का विवेकपूर्ण और उचित तरीका यह होगा कि उपर्युक्त कारकों को ध्यान में रखते हुए इसके विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों पर इसका मूल्यांकन किया जाए।

43. **माननीय सर्वोच्च न्यायालय** ने **समर घोष मामले** (उपर्युक्त) के कंडिका 101 में आगे टिप्पणी की है कि मार्गदर्शन के लिए कोई एकसमान मानक कभी निर्धारित नहीं किया जा सकता। हालांकि, माननीय न्यायालय ने कुछ मानव व्यवहार के उदाहरणों को गिनाना उचित समझा, जो "मानसिक क्रूरता" के मामलों से निपटने में प्रासंगिक हो सकते हैं, यह सावधानी के साथ कि ऐसे उदाहरण केवल दृष्टांतात्मक हैं और संपूर्ण नहीं हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गिनाए गए उदाहरण निम्नलिखित हैं:

" (i) पक्षकारों के संपूर्ण वैवाहिक जीवन पर विचार करने पर, तीव्र मानसिक दर्द, पीड़ा और कष्ट, जो पक्षकारों के लिए एक-दूसरे के साथ रहना असंभव बनाता है, मानसिक क्रूरता के व्यापक मापदंड के अंतर्गत आ सकता है।

(ii) पक्षकारों के संपूर्ण वैवाहिक जीवन का व्यापक मूल्यांकन करने पर, यह स्पष्ट हो जाता है कि स्थिति ऐसी है कि पीड़ित पक्ष से उचित रूप से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह ऐसे आचरण को सहन करे और दूसरे पक्ष के साथ रहना जारी रखे।

(iii) केवल ठंडापन या स्नेह की कमी क्रूरता के समान नहीं हो सकती, लेकिन बार-बार की गई असभ्य भाषा, चिड़चिड़ापन, उदासीनता और उपेक्षा ऐसी डिग्री तक पहुँच सकती है कि यह दूसरे पति या पत्नी के लिए वैवाहिक जीवन को पूरी तरह असहनीय बना दे।

(iv) मानसिक क्रूरता एक मन की स्थिति है। एक पति या पत्नी में दूसरे के आचरण के कारण लंबे समय तक गहरी पीड़ा, निराशा, हताशा की भावना मानसिक क्रूरता की ओर ले जा सकती है।

v) अपमानजनक और नीचा दिखाने वाले व्यवहार का निरंतर क्रम, जो पति या पत्नी के जीवन को यातना देना, असुविधाजनक करना या दुखद बनाना हो।

vi) एक पति या पत्नी का निरंतर अनुचित आचरण और व्यवहार जो दूसरे पति या पत्नी की शारीरिक और मानसिक

स्वास्थ्य को वास्तव में प्रभावित करता हो। शिकायत किए गए व्यवहार और परिणामी खतरे या आशंका बहुत गंभीर, पर्याप्त और वजनी होनी चाहिए।

vii) निरंतर निंदनीय आचरण, जानबूझकर उपेक्षा, उदासीनता या वैवाहिक दयालुता के सामान्य मानक से पूर्ण विचलन, जो मानसिक स्वास्थ्य को चोट पहुँचाता हो या परपीड़क आनंद प्राप्त करता हो, भी मानसिक क्रूरता के समान हो सकता है।

viii) आचरण केवल ईर्ष्या, स्वार्थ, अधिकारिता से कहीं अधिक होना चाहिए, जो नाखुशी और असंतोष और भावनात्मक अशांति का कारण बनता हो, मानसिक क्रूरता के आधार पर तलाक देने का आधार नहीं हो सकता।

(ix) केवल तुच्छ झुंझलाहटें, झगड़े, दैनिक जीवन में होने वाली वैवाहिक जीवन की सामान्य टूट-फूट मानसिक क्रूरता के आधार पर तलाक देने के लिए पर्याप्त नहीं होगी।

x) वैवाहिक जीवन को समग्र रूप से समीक्षा की जानी चाहिए और कई वर्षों में कुछ अलग-थलग घटनाएँ क्रूरता के समान नहीं होंगी। गलत आचरण को काफी लंबे समय तक निरंतर होना चाहिए, जहां संबंध इतने बिगड़ गए हों कि पति या पत्नी के कृत्यों और व्यवहार के कारण, पीड़ित पक्ष को दूसरे पक्ष के साथ और रहना अत्यंत कठिन लगता हो, यह मानसिक क्रूरता के समान हो सकता है।

xi) यदि एक पति बिना चिकित्सकीय कारणों और अपनी पत्नी की सहमति या जानकारी के बंध्याकरण की सर्जरी करवाता है

और इसी तरह, यदि पत्नी बिना चिकित्सकीय कारण या अपने पति की सहमति या जानकारी के वासेक्टॉमी या गर्भपात करवाती है, तो पति या पत्नी का ऐसा कृत्य मानसिक क्रूरता की ओर ले जा सकता है।

xii) बिना शारीरिक अक्षमता या वैध कारण के लंबे समय तक यौन संबंध से एकतरफा इंकार मानसिक क्रूरता के समान हो सकता है।

xiii) विवाह के बाद पति या पत्नी का एकतरफा निर्णय कि विवाह से संतान नहीं होगी, क्रूरता के समान हो सकता है।

xiv) जहाँ लगातार अलगाव की लंबी अवधि रही हो, वहाँ यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वैवाहिक बंधन अब सुधार के परे है। विवाह एक काल्पनिक बंधन बन जाता है, हालाँकि यह एक कानूनी बंधन द्वारा समर्थित है। ऐसे मामलों में, उस बंधन को तोड़ने से इनकार करके, कानून विवाह की पवित्रता की रक्षा नहीं करता; बल्कि, यह पक्षों की भावनाओं और संवेदनाओं के प्रति बहुत कम सम्मान प्रदर्शित करता है। ऐसी स्थितियों में, यह मानसिक क्रूरता को जन्म दे सकता है।"

44. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **रवि कुमार बनाम जुमला देवी**, जैसा कि **2010 एस.सी.सी.आर. 265** में प्रतिवेदित किया गया है, यह टिप्पणी की कि वैवाहिक संबंधों में, क्रूरता का अर्थ स्पष्ट रूप से पति-पत्नी के बीच आपसी सम्मान और समझ का अभाव है, जो रिश्ते को कड़वा बनाता है और अक्सर व्यवहार के विभिन्न प्रकोपों को जन्म देता है, जिन्हें क्रूरता कहा जा सकता है। कभी-कभी वैवाहिक संबंध में क्रूरता हिंसा का रूप ले सकती है, कभी-कभी यह एक अलग रूप ले सकती है। कभी-कभी, यह केवल एक दृष्टिकोण या

रवैया हो सकता है। कुछ स्थितियों में मौन भी क्रूरता के समान हो सकता है। इसलिए, वैवाहिक व्यवहार में क्रूरता किसी परिभाषा को चुनौती देती है और इसकी श्रेणी कभी बंद नहीं हो सकती। पति का अपनी पत्नी के प्रति क्रूर होना या पत्नी का अपने पति के प्रति क्रूर होना, दिए गए मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखकर और किसी पूर्व-निर्धारित कठोर सूत्र के बिना निर्धारित और आंका जाना चाहिए। वैवाहिक मामलों में क्रूरता अनंत प्रकार की हो सकती है। यह सूक्ष्म या क्रूर हो सकती है और इशारों और शब्दों के माध्यम से हो सकती है।

45. रामचंदर बनाम अनंता, जैसा कि **2015(11) एस.सी.सी. 539** में प्रतिवेदित किया गया है, के कंडिका 10 में, **माननीय सर्वोच्च न्यायालय** ने टिप्पणी की है कि धारा 13(1)(i-a) के प्रयोजन के लिए क्रूरता को एक पति या पत्नी द्वारा दूसरे के प्रति ऐसा व्यवहार माना जाएगा, जो बाद वाले के मन में यह उचित आशंका पैदा करता है कि दूसरे के साथ वैवाहिक संबंध जारी रखना उसके लिए सुरक्षित नहीं है। क्रूरता शारीरिक या मानसिक हो सकती है।

46. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **रामचंदर मामले** (उपर्युक्त) में आगे टिप्पणी की है कि क्रूरता की घटनाओं को अलग-अलग नहीं लिया जाना चाहिए। अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से उभरने वाले तथ्यों और परिस्थितियों का संचयी प्रभाव विचार में लिया जाना चाहिए ताकि यह उचित निष्कर्ष निकाला जा सके कि क्या वादी को दूसरे पति या पत्नी के आचरण के कारण मानसिक क्रूरता का सामना करना पड़ा है।

47. विनीता सक्सेना बनाम पंकज पंडित, जैसा कि **(2006) 3 एस.सी.सी. 778** में प्रतिवेदित किया गया है, में **माननीय सर्वोच्च न्यायालय** ने कंडिका 31 में टिप्पणी की है कि यह कई निर्णयों की श्रृंखला द्वारा स्थापित है कि मानसिक क्रूरता शारीरिक नुकसान से भी अधिक गंभीर चोट पहुंचा सकती है और पीड़ित अपीलकर्ता के मन में ऐसी आशंका

पैदा कर सकती है जैसी कि धारा में परिकल्पित है। इसे मामले के समग्र तथ्यों और पति-पत्नी के बीच वैवाहिक संबंधों के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए। क्रूरता माने जाने के लिए, पक्षकार के साथ ऐसा जानबूझकर किया गया व्यवहार होना चाहिए जिससे शरीर या मन को वास्तविक तथ्य के रूप में या आशंका के रूप में इस तरह से पीड़ा पहुँची हो कि पति/पत्नी का साथ-साथ रहना मामले की परिस्थितियों को देखते हुए हानिकारक या क्षतिपूर्ण हो।।

48. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **विनीता सक्सेना मामले** (उपर्युक्त) के कंडिका 32 में आगे टिप्पणी की है कि "क्रूरता" शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है और इसे मानवीय आचरण या मानव व्यवहार के संबंध में उपयोग किया गया है। यह वैवाहिक कर्तव्यों और दायित्वों के संबंध में आचरण है। यह एक पक्ष का ऐसा आचरण है जो दूसरे को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। क्रूरता मानसिक या शारीरिक, जानबूझकर या अनजाने में हो सकती है। कुछ मामले ऐसे हो सकते हैं जहां शिकायत किया गया आचरण स्वयं इतना खराब हो और प्रथम दृष्टया गैरकानूनी या अवैध हो। ऐसे मामलों में, दूसरे पति या पत्नी पर प्रभाव या हानिकारक प्रभाव की जांच करने या विचार करने की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे मामलों में, यदि आचरण स्वयं साबित हो जाता है या स्वीकार किया जाता है, तो क्रूरता स्थापित हो जाएगी।

49. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **विनीता सक्सेना मामले** (उपर्युक्त) के कंडिका 36 में आगे टिप्पणी की है कि विधि द्वारा परिभाषित न की गई क्रूरता की कानूनी अवधारणा को सामान्य रूप से ऐसे आचरण के रूप में वर्णित किया जाता है जो जीवन, अंग या स्वास्थ्य (शारीरिक और मानसिक) को खतरे में डालने वाला हो या ऐसी खतरे की उचित आशंका पैदा करता हो। क्रूरता के सभी सवालों में सामान्य नियम यह है कि संपूर्ण वैवाहिक संबंध पर विचार किया जाना चाहिए, यह नियम विशेष रूप से तब महत्वपूर्ण है जब क्रूरता हिंसक कृत्यों में नहीं, बल्कि हानिकारक निंदाओं, शिकायतों, आरोपों या तानों में हो। यह

मानसिक हो सकती है जैसे कि पत्नी के प्रति उदासीनता और ठंडापन, उसके साथ समय न बिताना, पत्नी के प्रति घृणा और तिरस्कार, या शारीरिक, जैसे हिंसा के कृत्य और बिना उचित कारण के यौन संबंध से परहेज। यह साबित करना होगा कि विवाह में एक पक्षकार ने, परिणामों की परवाह किए बिना, इस तरह से व्यवहार किया है कि दूसरे पति या पत्नी को परिस्थितियों में इसे सहन करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, और उस कदाचार ने स्वास्थ्य को चोट पहुंचाई हो या ऐसी चोट की उचित आशंका पैदा की हो। क्रूरता के मामले में दो पक्षों पर विचार करना होगा। अपीलकर्ता के दृष्टिकोण से, क्या इस अपीलकर्ता को इस आचरण को सहन करने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए? उत्तरदाता के दृष्टिकोण से, क्या यह आचरण क्षम्य था? फिर न्यायालय को यह तय करना होगा कि निंदनीय आचरण का कुल योग क्रूर था या नहीं। यह इस पर निर्भर करता है कि संचयी आचरण इतना गंभीर था कि एक तर्कसंगत व्यक्ति के दृष्टिकोण से, परिस्थितियों में उत्तरदाता के पास जो भी बहाना हो, उसे विचार करने के बाद, आचरण ऐसा है कि याचिकाकर्ता को इसे सहन करने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए।

50. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **विनीता सक्सेना मामले** (उपर्युक्त) के कंडिका 37 में आगे टिप्पणी की है कि उक्त प्रावधान के प्रयोजनों के लिए आवश्यक मानसिक क्रूरता क्या है, यह ऐसी घटनाओं की संख्यात्मक गणना या केवल ऐसे आचरण के निरंतर क्रम पर निर्भर नहीं करेगा, बल्कि वास्तव में इसकी तीव्रता, गंभीरता और कलंकात्मक प्रभाव पर निर्भर करेगा जब एक बार भी ऐसा किया जाए और एक अनुकूल वैवाहिक घर को बनाए रखने के लिए आवश्यक मानसिक दृष्टिकोण पर इसके हानिकारक प्रभाव पर निर्भर करेगा।

51. माननीय उच्चतम न्यायालय ने आगे कहा है कि **विनीता सक्सेना मामले** (उपर्युक्त) में आगे टिप्पणी की है कि यदि ताने, शिकायतें और निंदाएँ केवल सामान्य प्रकृति की हैं, तो न्यायालय को शायद यह और प्रश्न विचार करने की आवश्यकता हो कि क्या इनका समय के साथ निरंतरता या दृढ़ता, जो सामान्य रूप से इतना गंभीर नहीं होगा, उसे इतना

हानिकारक और दर्दनाक बना देता है कि जिस पति या पत्नी पर इसका आरोप लगाया गया है, वह वास्तव में और उचित रूप से यह निष्कर्ष निकाले कि वैवाहिक घर का रखरखाव अब संभव नहीं है।

52. वर्तमान मामले पर आते हुए, हम पाते हैं कि पिछले याचिका, जो प्रदर्श-2 है, में क्रूरता को तलाक के आधार के रूप में अभिकथित नहीं किया गया था। हम यह भी पाते हैं कि वर्तमान तलाक याचिका में क्रूरता के संबंध में केवल यह अभिकथन है कि उत्तरदाता/पत्नी अपीलकर्ता/वादी के साथ समय बिताने से इंकार कर रही है। उसके द्वारा निर्मित आचरण और परिस्थितियां अपमानजनक हैं तथा उसके लिए मानसिक क्रूरता का कारण बन रही हैं। यह भी अभिकथित किया गया है कि उत्तरदाता/पत्नी द्वारा दायर झूठे आपराधिक मामले के कारण अपीलकर्ता/वादी का जीवन दुखद हो गया है और वह निजी और सार्वजनिक जीवन में अपमानित महसूस कर रहा है। अतः, वह उत्तरदाता/पत्नी के साथ रहने की स्थिति में नहीं है। अ.सा.-2, जिनकी जांच 30.08.2016 को की गई, ने साक्ष्य दिया है कि उत्तरदाता/पत्नी एक सरकारी अस्पताल में नर्स के रूप में कार्यरत है और वह अपीलकर्ता/वादी से 19 वर्षों से अलग रह रही है और पक्षकारों के बीच वैवाहिक जीवन पूरी तरह समाप्त हो चुका है। अ.सा.-2, सब्जो साची घोष ने साक्ष्य दिया है कि उन्हें नहीं पता कि उत्तरदाता/पत्नी अपीलकर्ता/वादी से अलग क्यों रह रही है। अपीलकर्ता/वादी, जिनकी अ.सा.-3 के रूप में जांच की गई, ने न तो अभिवचनों में और न ही साक्ष्य में क्रूरता की कोई विशिष्ट घटना दी है। हालांकि, उन्होंने साक्ष्य दिया है कि उत्तरदाता-पत्नी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए के अंतर्गत दायर शिकायत वाद खारिज हो चुका है। लेकिन, उन्होंने इस दावे के समर्थन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया और यह स्पष्ट नहीं है कि शिकायत वाद कैसे खारिज हुआ। यह भी ध्यान देने योग्य है कि प्रदर्श-2, जो अपीलकर्ता-वादी द्वारा दायर पिछले तलाक मामले का वादपत्र है, के अनुसार, उन्होंने उत्तरदाता/पत्नी के खिलाफ क्रूरता का कोई आरोप नहीं लगाया था और वादपत्र में दिए गए पते से यह भी प्रतीत होता है

कि पिछले तलाक याचिका दायर करने के समय भी वह अलग रह रही थी। यह स्पष्ट करता है कि अपीलकर्ता/वादी ने क्रूरता के सामान्य और अस्पष्ट आरोपों को छोड़कर क्रूरता की कोई घटना क्यों नहीं दी। पति के समाज से अलग होने का अर्थ यह नहीं है कि वह क्रूरता है, यदि पति या पत्नी के दूसरे पति या पत्नी के समाज से अलग होने का कोई वैध कारण हो। झूठा आपराधिक मामला दायर करना क्रूरता के समान हो सकता है, लेकिन अभिलेख पर उपलब्ध अभिवचनों और साक्ष्यों से यह पुख्ता सबूत नहीं है कि उत्तरदाता-पत्नी द्वारा दायर आपराधिक मामला खारिज हो गया है और यदि यह खारिज हुआ है, तो कैसे और किस कारण से खारिज हुआ है। ऐसी स्थिति में, यह राय बनाना बहुत कठिन है कि उत्तरदाता-पत्नी द्वारा दायर आपराधिक मामला झूठा था।

53. इस प्रकार, अभिवचनों और अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों की समग्रता के दृष्टिगत, हम पाते हैं कि अपीलकर्ता/पति ने उत्तरदाता/पत्नी के किसी भी कथित कदाचार को साबित नहीं किया है जो वैवाहिक जीवन की सामान्य "टूट-फूट" से अधिक गंभीर या "गंभीर और वजनी" हो, जिसने उसके जीवन, अंग या स्वास्थ्य, शारीरिक या मानसिक, को खतरे में डाला हो, या ऐसी उचित आशंका उत्पन्न की हो जिसके कारण उसके लिए उत्तरदाता/पत्नी के साथ वैवाहिक जीवन जारी रखना असुरक्षित हो। इस प्रकार, हम पाते हैं कि उत्तरदाता/पत्नी द्वारा अपीलकर्ता-पति के प्रति कोई कानूनी क्रूरता नहीं की गई है जो उसे तलाक की डिक्री का हकदार बनाए।

54. अतः, यह बिंदु उत्तरदाता/पत्नी के पक्ष में और अपीलकर्ता/पति के विरुद्ध तय किया जाता है।

बिंदु सं 2

55. अब, हम बिंदु सं 2 पर विचार करें, जो परित्याग से संबंधित है। हालांकि, इसे विचार करने से पहले, इस विषय पर वैधानिक प्रावधानों और केस कानूनों को देखना फिर से अनिवार्य होगा।

56. परित्याग को हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1)(ib) के तहत तलाक के आधार के रूप में प्रदान किया गया है। प्रावधानों के अनुसार, यदि दूसरा पक्ष याचिकाकर्ता को याचिका प्रस्तुत करने से ठीक पहले कम से कम दो वर्ष की निरंतर अवधि के लिए परित्यक्त करता है, तो पति या पत्नी में से किसी एक द्वारा प्रस्तुत याचिका पर विवाह को तलाक की डिक्री द्वारा भंग किया जा सकता है। स्पष्टीकरण के अनुसार, "परित्याग" अभिव्यक्ति का अर्थ है कि विवाह के दूसरे पक्ष द्वारा याचिकाकर्ता का बिना उचित कारण और उसकी सहमति के या उसकी इच्छा के विरुद्ध परित्याग, और इसमें विवाह के दूसरे पक्ष द्वारा याचिकाकर्ता की जानबूझकर उपेक्षा शामिल है, और इसके व्याकरणिक रूपांतर और संज्ञानात्मक अभिव्यक्तियों की तदनुसार व्याख्या की जाएगी।

57. बिपिनचंद्र जयसिंहभाई शाह बनाम प्रभावती, जैसा कि **ए.आई.आर. 1957 एस.सी. 176** में प्रतिवेदित किया गया है, में **माननीय सर्वोच्च न्यायालय** ने टिप्पणी की है कि स्थायित्व की गुणवत्ता परित्याग को जानबूझकर अलगाव से अलग करने वाला एक आवश्यक तत्व है। यदि एक पति या पत्नी दूसरे पति या पत्नी को अस्थायी उत्तेजना की स्थिति में, उदाहरण के लिए, क्रोध या घृणा में, स्थायी रूप से सहवास समाप्त करने के इरादे के बिना छोड़ता है, तो यह परित्याग नहीं होगा। परित्याग के अपराध के लिए, परित्याग करने वाले पति या पत्नी के दृष्टिकोण से, दो आवश्यक शर्तें होनी चाहिए, अर्थात्, (1) अलगाव का तथ्य, और (2) सहवास को स्थायी रूप से समाप्त करने का इरादा (अभित्यजन का आशय)। इसी तरह, परित्यक्त पति या पत्नी के दृष्टिकोण से भी दो तत्व आवश्यक हैं: (1) सहमति की अनुपस्थिति, और (2) वैवाहिक घर छोड़ने वाले पति या पत्नी को उपरोक्त आवश्यक इरादा बनाने के लिए उचित कारण देने वाले आचरण की अनुपस्थिति। तलाक के लिए याचिकाकर्ता को इन तत्वों को दोनों पक्षों में क्रमशः साबित करने का बोझ वहन करना पड़ता है। उसी कंडिका में **माननीय सर्वोच्च न्यायालय** ने आगे टिप्पणी की है कि परित्याग प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से निकाला जाने वाला निष्कर्ष है। निष्कर्ष कुछ

तथ्यों से निकाला जा सकता है जो किसी अन्य मामले में उसी निष्कर्ष तक ले जाने में सक्षम नहीं हो सकते; अर्थात्, तथ्यों को उन कृत्यों या आचरण और इरादे की अभिव्यक्ति द्वारा प्रकट होने वाले उद्देश्य के रूप में देखा जाना चाहिए, जो वास्तविक अलगाव से पहले और बाद दोनों में हो। यदि वास्तव में अलगाव हुआ है, तो हमेशा आवश्यक प्रश्न यह है कि क्या वह कृत्य एनिमस डेसेरेन्डी (अभित्यजन का आशय) के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। परित्याग का अपराध तब शुरू होता है जब अलगाव का तथ्य और एनिमस डेसेरेन्डी (अभित्यजन का आशय) एक साथ मौजूद हों। लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि वे एक ही समय में शुरू हों। वास्तविक अलगाव बिना आवश्यक इरादे के शुरू हो सकता है या यह हो सकता है कि अलगाव और एनिमस डेसेरेन्डी (अभित्यजन का आशय) समय में एक साथ हों; उदाहरण के लिए, जब अलग होने वाला पति या पत्नी वैवाहिक घर को स्पष्ट या निहित इरादे के साथ छोड़ता है, जो सहवास को स्थायी रूप से समाप्त करने का हो।

58. बिपिनचंद्र जयसिंहभाई शाह मामले (उपर्युक्त) का अनुसरण करते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **लछमन उतमचंद किरपलानी बनाम मीना**, जैसा कि **ए.आई.आर. 1964 एस.सी. 40** में प्रतिवेदित किया गया है, में माना कि परित्याग का सार यह है कि एक पति या पत्नी द्वारा दूसरे को बिना उसकी सहमति के और बिना उचित कारण के जानबूझकर स्थायी रूप से छोड़ना और परित्याग करना। परित्याग के अपराध के लिए, परित्याग करने वाले पति या पत्नी के दृष्टिकोण से, दो आवश्यक शर्तें होनी चाहिए (1) अलगाव का तथ्य, और (2) सहवास को स्थायी रूप से समाप्त करने का इरादा (*एनिमस डेसेरेन्डी*)। इसी तरह, परित्यक्त पति या पत्नी के दृष्टिकोण से भी दो तत्व आवश्यक हैं: (1) सहमति की अनुपस्थिति, और (2) वैवाहिक घर छोड़ने वाले पति या पत्नी को उपरोक्त आवश्यक इरादा बनाने के लिए उचित कारण देने वाले आचरण की अनुपस्थिति। परित्याग को साबित करने के लिए निष्कर्ष कुछ तथ्यों से निकाला जा सकता है जो किसी अन्य

मामले में उसी निष्कर्ष तक ले जाने में सक्षम नहीं हो सकते; अर्थात्, तथ्यों को उन कृत्यों या आचरण और इरादे की अभिव्यक्ति द्वारा प्रकट होने वाले उद्देश्य के रूप में देखा जाना चाहिए, जो वास्तविक अलगाव से पहले और बाद दोनों में हो।

59. **माननीय सर्वोच्च न्यायालय** ने **सावित्री पांडे बनाम प्रेम चंद्र पांडे**, जैसा कि **2002(2) एस.सी.सी. 73** में प्रतिवेदित किया गया है, के कंडिका 8 में टिप्पणी की है कि अधिनियम के तहत तलाक की मांग के लिए "परित्याग" का अर्थ है एक पति या पत्नी द्वारा दूसरे को बिना उसकी सहमति और बिना उचित कारण के जानबूझकर स्थायी रूप से छोड़ना और परित्याग करना। दूसरे शब्दों में, यह विवाह के दायित्वों का पूर्ण अस्वीकरण है। परित्याग किसी स्थान से हटना नहीं, बल्कि एक स्थिति से हटना है। इसलिए, परित्याग का अर्थ है वैवाहिक दायित्वों से हटना, अर्थात् पक्षकारों के बीच सहवास को अनुमति न देना, अनुमति न देना और सुविधा न देना। परित्याग के साक्ष्य को विवाह की अवधारणा को ध्यान में रखकर विचार किया जाना चाहिए, जो कानून में समाज में पुरुष और महिला के बीच यौन संबंध को वैध बनाता है, जो नस्ल के निरंतरता, अवैधता को रोकने के लिए जुनून में वैध भोग की अनुमति देता है और बच्चों के प्रजनन के लिए है। परित्याग अपने आप में एक एकल कृत्य नहीं है, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के तहत निर्धारित होने वाला निरंतर आचरण है।

60. **माननीय सर्वोच्च न्यायालय** ने **देबानंद तमुली बनाम काकुमोनी कटकी**, जैसा कि **(2022) 5 एस.सी.सी. 459** में प्रतिवेदित किया गया है, के कंडिका 7 में टिप्पणी की है कि इस न्यायालय द्वारा लगातार निर्धारित कानून यह है कि परित्याग का अर्थ है एक पति या पत्नी द्वारा दूसरे को बिना उसकी सहमति और बिना उचित कारण के जानबूझकर परित्याग करना। परित्यक्त पति या पत्नी को यह साबित करना होगा कि अलगाव का तथ्य है और परित्याग करने वाले पति या पत्नी की ओर से सहवास को स्थायी रूप से समाप्त करने का इरादा है। दूसरे शब्दों में, परित्याग करने वाले पति या पत्नी में एनिमस डेसेरेन्डी

(अभित्यजन का आशय) होना चाहिए। परित्यक्त पति या पत्नी की ओर से सहमति की अनुपस्थिति होनी चाहिए और परित्यक्त पति या पत्नी के आचरण ने परित्याग करने वाले पति या पत्नी को वैवाहिक घर छोड़ने के लिए आवश्यक इरादा बनाने के लिए उचित कारण नहीं दिया होना चाहिए। इस न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण अधिनियम 68, 1976 द्वारा धारा 13 की उप-धारा (1) में जोड़े गए स्पष्टीकरण में शामिल किया गया है।

61. **वर्तमान मामले पर आते हुए**, हम पाते हैं कि वादपत्र में यह अभिकथन नहीं है कि उत्तरदाता ने अपीलकर्ता/वादी के समाज से कब हटना शुरू किया और न ही वादपत्र में यह अभिकथन है कि तलाक के लिए वादपत्र प्रस्तुत करने के समय उसने कितने वर्षों तक अपीलकर्ता/वादी को परित्यक्त किया है। इसके अलावा, परित्याग का यह आधार पिछले तलाक याचिका, जो वैवाहिक वाद संख्या 30/2000 थी, में भी अभिकथित नहीं किया गया था। अपीलकर्ता/वादी की ओर से जांचे गए गवाहों के साक्ष्य में, हम पाते हैं कि अ.सा.-1, परदेशी कामती के अनुसार, उत्तरदाता/पत्नी 19 वर्षों से अलग रह रही है। लेकिन, उन्होंने अलग रहने के कारण के बारे में कुछ भी साक्ष्य नहीं दिया। अ.सा.-1 ने साक्ष्य दिया है कि उन्हें नहीं पता कि उत्तरदाता/पत्नी क्यों अलग रह रही है और यहां तक कि अपीलकर्ता/वादी, जिनकी अ.सा.-3 के रूप में जांच की गई, इस मुद्दे पर चुप रहे। उन्होंने न तो अभिकथन किया और न ही साक्ष्य दिया कि उत्तरदाता-पत्नी कब से अलग रह रही है और किस कारण से। उन्होंने अलग रहने के कारण के बारे में भी साक्ष्य नहीं दिया।

62. इस प्रकार, अपीलकर्ता/पति यह साबित करने में विफल रहा है कि उत्तरदाता/पत्नी ने वर्तमान याचिका प्रस्तुत करने के समय उसकी सहमति के बिना और बिना उचित कारण के सहवास को स्थायी रूप से समाप्त करने के इरादे से दो वर्ष से अधिक समय तक उसे परित्यक्त किया है।

63. अतः, यह बिंदु भी अपीलकर्ता/पति के विरुद्ध और उत्तरदाता/पत्नी के पक्ष में तय किया जाता है।

बिंदु सं 3

64. अब हम बिंदु संख्या 3 पर आते हैं, जो व्यभिचार के आधार से संबंधित है। हम पाते हैं कि अभिवचनों में उत्तरदाता/पत्नी के व्यभिचारी जीवन के बारे में एक शब्द भी नहीं है, न ही कथित व्यभिचारी को पारिवारिक न्यायालय के समक्ष उत्तरदाता के रूप में शामिल किया गया है। इसके अलावा, यह कानून का स्थापित सिद्धांत है कि अभिवचनों से परे साक्ष्य को राहत देने के लिए विचार नहीं किया जा सकता।

65. विभिन्न न्यायिक निर्णयों के प्रकाश में, यह कानून का स्थापित सिद्धांत है कि अभिवचनों से परे प्रस्तुत साक्ष्य को अस्वीकार किया जाना चाहिए और याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई राहत देने के लिए इसे विचार नहीं किया जा सकता।

66. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम नरेशकुमार बद्रीकुमार जगद और अन्य**, जैसा कि **(2011) 12 एस.सी.सी. 695** में प्रतिवेदित किया गया है, के कंडिका 12 में, **ट्रोजन एंड कंपनी बनाम नागप्पा चेट्टियार** जैसा कि **ए.आई.आर. 1953 एस.सी. 235** में प्रतिवेदित है , **महाराष्ट्र राज्य बनाम हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड** जैसा कि **2010 4 एस.सी.सी. 518** में प्रतिवेदित है, और **कल्याण सिंह चौहान बनाम सी.पी. जोशी** जैसा कि **(2011) 11 एस.सी.सी. 786** में प्रतिवेदित है, का उल्लेख करने के बाद टिप्पणी की है कि अभिवचन और विवरण न्यायालय को विचारण में पक्षकारों के अधिकारों को तय करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हैं। इसलिए, अभिवचन विवाद को सीमित करने और संबंधित पक्षकारों को मुद्दे पर सूचित करने में न्यायालय की अधिक सहायता करते हैं, ताकि पक्षकार उक्त मुद्दे पर उचित साक्ष्य प्रस्तुत कर सकें। यह आगे टिप्पणी की गई है कि एक स्थापित कानूनी सिद्धांत के रूप में, अभिवचनों पर आधारित न होने वाली राहत प्रदान नहीं की जानी चाहिए। किसी मामले का निर्णय पक्षकारों के अभिवचनों से बाहर के आधारों पर आधारित नहीं हो सकता। अभिवचन और मुद्दे

पक्षकारों के बीच वास्तविक विवाद को निर्धारित करने, संघर्ष के क्षेत्र को सीमित करने और यह देखने के लिए हैं कि दोनों पक्ष कहाँ भिन्न हैं।

67. प्रकाश रतन लाल बनाम मन्की राम, जैसा कि आई.एल.आर. (2010) III दिल्ली 315 में प्रतिवेदित किया गया है, में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने **राम सरूप गुप्ता द्वारा विधिक प्रतिनिधियों बनाम बिशन नारायण इंटर कॉलेज** जैसा कि **(1987) 2 एस.सी.सी. 555)** में प्रतिवेदित है और **हरिहर प्रसाद सिंह बनाम बालमिकी प्रसाद सिंह** जैसा कि **(1975) 1 एस.सी.सी. 212)** में प्रतिवेदित है, का उल्लेख किया और निर्णय के कंडिका 4 में टिप्पणी की कि अभिवचनों का एकमात्र उद्देश्य पक्षकारों को एक रुख पर बांधना है। जब वादी कुछ आरोप लगाता है, तो उत्तरदाता को प्रत्येक आरोप के लिए विशेष रूप से अपनी रक्षा प्रकट करनी चाहिए और न्यायालय को सच्चे तथ्य बताने चाहिए, और एक बार जब दोनों पक्षों द्वारा तथ्य बताए जाते हैं, तो न्यायालय को मुद्दे तैयार करने और पक्षकारों को साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए कहना होता है। यह स्थापित कानून है कि पक्षकार अपने अभिवचनों तक सीमित साक्ष्य प्रस्तुत कर सकते हैं और साक्ष्य प्रस्तुत करते समय अभिवचनों से परे नहीं जा सकते। यदि पक्षकारों को अभिवचनों से परे साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाती है, तो अभिवचनों की पवित्रता समाप्त हो जाती है और अभिवचन दाखिल करने का पूरा उद्देश्य भी विफल हो जाता है। इसके पीछे एक अन्य उद्देश्य यह है कि कोई भी पक्षकार आश्चर्यचकित न हो और उत्तरदाता द्वारा लिखित बयान में उल्लिखित न किए गए नए तथ्यों को साक्ष्य के माध्यम से नहीं लाया जा सकता। कानून अभिवचनों के संशोधन की प्रक्रिया प्रदान करता है और यदि कोई पक्ष अभिलेख पर कोई नया तथ्य लाना चाहता है, तो वह अभिवचनों में संशोधन कर सकता है, लेकिन अभिवचनों में संशोधन के बिना, किसी पक्ष को अभिवचनों से परे साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

68. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **बच्चज नाहर बनाम नीलिमा मंडल और अन्य**, जैसा कि **(2008) 17 एस.सी.सी 491** में प्रतिवेदित किया गया है, के कंडिका 12 में

टिप्पणी की है कि अभिवचनों और मुद्दों का उद्देश्य और लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि वादकारी सभी मुद्दों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करके विचारण में आएं और विचारण के दौरान मामले का विस्तार या आधारों को बदलने से रोका जाए। इसका उद्देश्य यह भी है कि प्रत्येक पक्ष उन सवालों के प्रति पूरी तरह जागरूक हो जो उठाए जा सकते हैं या विचार किए जा सकते हैं, ताकि उनके पास न्यायालय के समक्ष विचार के लिए मुद्दों के लिए उपयुक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर हो। यह आगे टिप्पणी की गई है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बार-बार माना है कि अभिवचन का उद्देश्य प्रत्येक पक्ष को दूसरे पक्ष के मामले की जानकारी देना है, ताकि उसका ठीक से सामना किया जा सके। इससे न्यायालय यह निर्धारित कर सकें कि वास्तव में पक्षकारों के बीच क्या मुद्दा है, और वाद के दौरान किसी विशेष कारण से होने वाले विचलन को रोका जा सके। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय के कंडिका 10 में आगे निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया:

> *"10. इस मामले में, उच्च न्यायालय ने, वादी को मुकदमेबाजी के एक और दौर में धकेलने से होने वाली देरी और कठिनाई को कम करने के अपने स्पष्ट उत्साह में, एक ऐसा निर्णय दिया है जो दीवानी प्रक्रिया के कई मूलभूत नियमों का उल्लंघन करता है। उल्लंघन किए गए नियम हैं:*
>
> > *(i) अभिवचनों में कभी न उठाए गए दावे पर किसी भी मात्रा में साक्ष्य को विचार नहीं किया जा सकता। ऐसा प्रश्न जो अभिवचनों से उत्पन्न नहीं हुआ और जो किसी मुद्दे का विषय-वस्तु नहीं था, उसे न्यायालय द्वारा तय नहीं किया जा सकता।*
> >
> > *(ii) न्यायालय ऐसा मामला नहीं बना सकता जो अभिकथित नहीं किया गया हो। न्यायालय को अपने*

निर्णय को अभिवचनों में उठाए गए प्रश्न तक सीमित रखना चाहिए। न ही वह ऐसी राहत दे सकता है जो दावा नहीं की गई हो और जो वादपत्र में कथित तथ्यों और कार्रवाई के कारण से प्रवाहित नहीं होती।

(iii) तथ्यात्मक मुद्दा पहली बार दूसरी अपील में नहीं उठाया या विचार नहीं किया जा सकता।"

69. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **राम सरूप गुप्ता मामले** (उपर्युक्त) के कंडिका 6 में टिप्पणी की है कि यह अच्छी तरह से स्थापित है कि अभिवचन की अनुपस्थिति में, पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य, यदि कोई हो, पर विचार नहीं किया जा सकता। यह भी समान रूप से स्थापित है कि किसी भी पक्ष को अपने अभिवचनों से परे जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और सभी आवश्यक और महत्वपूर्ण तथ्यों को पक्षकार द्वारा अपने द्वारा स्थापित मामले के समर्थन में अभिकथित करना चाहिए।

70. अतः, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, अभिवचनों से परे प्रस्तुत साक्ष्य को अस्वीकार किया जाना चाहिए और इसे कथित तलाक के आधारों के साक्ष्य के रूप में विचार नहीं किया जा सकता।

71. इस प्रकार, हम पाते हैं कि वर्तमान अपील में कोई योग्यता नहीं है जो आक्षेपित निर्णय में हस्तक्षेप की आवश्यकता को उचित ठहराए। पारिवारिक न्यायालय ने अपीलकर्ता के तलाक की मांग वाले वैवाहिक मामले को सही ढंग से खारिज किया है। तदनुसार, वर्तमान अपील खारिज की जाती है, और आक्षेपित निर्णय को बरकरार रखा जाता है। दोनों पक्ष अपने-अपने खर्च वहन करेंगे। तदनुसार डिक्री तैयार की जाए।

72. महानिबंधक को निर्देश दिया जाता है कि इस निर्णय की एक प्रति सभी पारिवारिक न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों के बीच वितरित की जाए और बिहार न्यायिक अकादमी के निदेशक को एक प्रति भेजी जाए।

(जितेंद्र कुमार, न्यायमूर्ति)

(पी. बी. भजंत्री ,न्यायमूर्ति)

चंदन/अमरेंद्र

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालय, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।